



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

26 चैत्र 1941 (श10)  
(सं० पटना 548) पटना, मंगलवार, 16 अप्रैल 2019

---

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना  
5 अप्रैल 2019

सं० पर्या०/वन (मु०)-09/2019-378(ई)/प०व०—माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन से सम्बन्धित मामले, O.A. No. 606/2018 में दिनांक 16.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) का गठन निम्नवत किया जाता है :—

- 1 जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)
- 2 पुलिस अधीक्षक
- 3 वरीयतम वन प्रमंडल पदाधिकारी (सदस्य सचिव)
- 4 अध्यक्ष, जिला विधि सेवाएँ प्राधिकरण (District Legal Services Authority) द्वारा नामित सदस्य
- 5 असैनिक शल्य चिकित्सक
- 6 जिलान्तर्गत सभी शहरी निकायों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त
- 7 जिला पंचायती राज पदाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)
- 8 कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- 9 राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा नामित सदस्य

टास्क फोर्स अपने-अपने जिले में शैक्षणिक, धर्मिक एवं सामाजिक संस्थानों जिसमें स्थानीय इको-क्लब भी शामिल हों, की सहायता से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों से सम्बन्धित जागरुकता फैलाने का कार्य करेगी।

यह टास्क फोर्स दो महीने में एक बार बैठक करेगी तथा अपना प्रतिवेदन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति को प्रस्तुत करेगी। टास्क फोर्स की बैठक आयोजित करने एवं कार्यवाही प्रतिवेदन निर्गत करने की कार्यवाही सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

जिला विधि सेवाएँ प्राधिकरण का शामिल होना विधि सेवाएँ प्राधिकार अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय विधि सेवाएँ प्राधिकरण की प्रशासनिक स्वीकृति पर आधारित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
दीपक कुमार सिंह,  
सरकार के प्रधान सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>